भारत-कोरिया संबंध होंगे मजबूत : गोयल

व्यापार मंत्री येओ हान-कू के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा की

यह समझौता दोनों देशों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है

नई दिल्ली, 20 अप्रैल भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और संसाधन मंत्रालय के व्यापार मंत्री येओ हान-कू के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा की और इसे उन्नत बनाने के लिए वार्ताओं को पुनः शुरू करने पर विस्तृत चर्चा की. बैठक के बाद मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए वार्ता को फिर से शुरू करने और उसमें सुधार लाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया. उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में यह समझौता दोनों देशों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है.

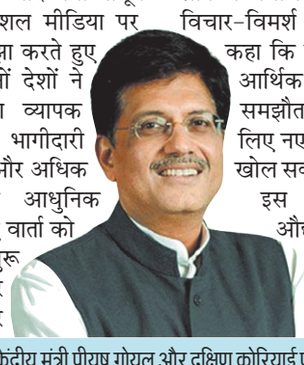

इस बैठक में औद्योगिक सहयोग, हरित ऊर्जा और डिजिटल व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया. दोनों देशों ने माना कि भविष्य की अर्थव्यवस्था में तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, और इन क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना दोनों पक्षों के लिए लाभकारी साबित होगा.

दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री येओ हान-कू, राष्ट्रपति ली जेई मीयूंग के साथ भारत के दौरे पर आए हैं. उनके साथ कोरिया के उद्योग और व्यवसाय जगत का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है, जो भारत के साथ व्यापार और निवेश के नए अवसरों की तलाश कर रहा है. इस यात्रा को दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने के रूप में देखा जा रहा है.

> इसी क्रम में, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल आज शाम एक महत्वपूर्ण उद्योग संवाद में भी भाग लेंगे. इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख उद्यमी और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस बैठक में व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी के नए रास्तों पर चर्चा होने की उम्मीद है. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता जनवरी 2010 से प्रभावी है, लेकिन बदलते वैश्विक व्यापार ढांचे और नई आर्थिक जरूरतों को देखते हुए इसे और अधिक आधुनिक और व्यापक बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

लिकर स्टॉक्स में तेजी के संकेत

नई दिल्ली, 20 अप्रैल भारतीय शेयर बाजार में लिकर कंपनियों के स्टॉक्स एक बार फिर निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनते नजर आ रहे हैं. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म एवेंडस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश की पांच प्रमुख शराब कंपनियों के शेयरों में आने वाले समय में 31% तक की उल्लेखनीय तेजी देखने को मिल सकती है. रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रीमियमाइजेशन का बढ़ता रुझान, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं और मजबूत मांग इस सेक्टर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. ब्रोकरेज के मुताबिक, भारत में शराब उद्योग अब केवल एक सामान्य उपभोग श्रेणी नहीं रहा, बल्कि यह तेजी से लाइफस्टाइल और सामाजिक आकांक्षाओं से जुड़ा बाजार बनता जा रहा है. खासकर युवाओं में प्रीमियम और ब्रांडेड उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है.

एसजीबी निवेशकों के लिए एग्जिट मौका

पांच साल बाद मिलती है एग्जिट की सुविधा

ब्याज और कैपिटल गेन पर अलग-अलग टैक्स नियम लागू

नई दिल्ली, 20 अप्रैल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों के लिए राहत भरी खबर आई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 सीरीज के निवेशकों के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन यानी समय से पहले निकासी की विंडो खोल दी है. इस फैसले से उन निवेशकों को बड़ा फायदा मिल सकता है, जो अब अपने निवेश से बाहर निकलकर मुनाफा कमाना चाहते हैं.

आरबीआई द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस सीरीज के बॉन्ड के लिए रिडेम्पशन प्राइस 15,254 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है. यह कीमत इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी 24 कैरेट सोने की पिछले तीन कारोबारी दिनों की औसत कीमत के आधार पर तय की जाती है.

अगर इस बॉन्ड के इश्यू प्राइस पर नजर डालें, तो इसे 2020 में 5,051 रुपये प्रति यूनिट के भाव पर जारी किया गया था. ऐसे में मौजूदा रिडेम्पशन प्राइस के हिसाब से निवेशकों को लगभग 205 प्रतिशत तक का शानदार रिटर्न मिल सकता है. यह रिटर्न पारंपरिक निवेश विकल्पों की तुलना में काफी आकर्षक माना जा रहा है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की एक खासियत यह भी है कि इसमें निवेश करने पर सरकार की ओर से सालाना 2.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर मिलती है.

> हालांकि, निवेशकों को टैक्स नियमों को समझना भी जरूरी है. बजट 2026 के बाद लागू नियमों के अनुसार, यदि कोई निवेशक बॉन्ड को उसकी पूर्ण अवधि यानी मैच्योरिटी तक होल्ड करता है, तो उस पर होने वाला कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. वहीं, अगर निवेशक समय से पहले बॉन्ड को भुनाता है, तो टैक्स नियम अलग हो जाते हैं. 12 महीने से अधिक समय तक होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है, जबकि कम अवधि के लिए निवेश रखने पर लाभ निवेशक के आयकर स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है.

मध्य पूर्व तनाव से तेल में उछाल

क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचा

नई दिल्ली, 20 अप्रैल मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर देखने को मिला है, जहां कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है.

पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने और आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ने के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजारों में चिंता बढ़ गई है. सोमवार को ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड वायदा में तेज उछाल देखा गया और यह 7.18 प्रतिशत तक बढ़कर 96.87 डॉलर प्रति बैरल के इंट्रा-डे उच्च स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड में भी 8.76 प्रतिशत की भारी तेजी दर्ज की गई और यह 91.20 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. इस तेज बढ़त ने ऊर्जा बाजार में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है.

भारत में भी इस वैश्विक उछाल का असर साफ दिखाई दिया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कच्चे तेल की कीमतों में 6.72 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद यह 8,289 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया. तेल कीमतों में इस बढ़ोतरी से आने वाले समय में महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, खासकर पेट्रोल-डीजल और परिवहन लागत में बढ़ोतरी की संभावना के चलते.विशेषज्ञों के अनुसार, इस तेजी की मुख्य वजह ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता तनाव है.

> इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान इस रणनीतिक मार्ग को बंद कर अमेरिका पर दबाव नहीं बना सकता. वहीं, ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को युद्धविराम का उल्लंघन बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अपनी नौसेना को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अमेरिका द्वारा एक ईरानी कार्गो जहाज को जब्त करने की खबर सामने आई. इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है. और

पीपीएफ खाता बंद करना पड़ सकता है भारी

नई दिल्ली, 20 अप्रैल.भारत में लागू हुए नए लेबर कोड के बाद कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी, भविष्य की बचत और रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा. अब सभी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि कर्मचारी का बेसिक वेतन कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत हो.

अब तक कई कंपनियां टैक्स और लागत प्रबंधन के लिए बेसिक सैलरी को कम रखती थीं और बाकी हिस्से को ।क्र कन्वेयंस, बोनस और अन्य भत्तों के रूप में देती थीं. लेकिन नए नियमों के तहत यदि कुल सैलरी

में भत्तों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है, तो उस अंतर को बेसिक पे में शामिल करना होगा. इसका सीधा असर प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी योगदान पर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही बेसिक वेतन पर आधारित होते हैं. जब बेसिक वेतन बढ़ेगा तो कर्मचारी और कंपनी दोनों का क्क्न योगदान बढ़ जाएगा. इससे हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ भविष्य के लिए जमा होने वाली बचत जैसे क्क्न और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होगी.

शेयरों में लिवाली से चढ़े प्रमुख सूचकांक

26.76 अंक चढ़ा सेंसेक्स

11.30 अंक ऊपर रहा निफ्टी

मुंबई, 20 अप्रैल बैंकिंग शेयरों में लिवाली से सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त में बंद हुए.

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 26.76 अंक (0.03 प्रतिशत) चढ़कर 78,520.30 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 11.30 अंक यानी 0.05 प्रतिशत ऊपर 24,364.85 अंक पर पहुंच गया.

बाजार में आज काफी-उतार चढ़ाव देखा गया. विशेषकर शुरुआती कारोबार में बढ़त में खुलने के बाद प्रमुख सूचकांक पिछले

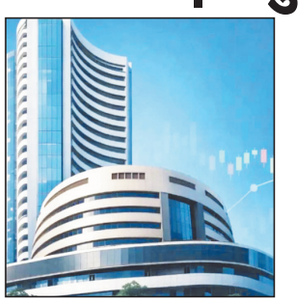

कारोबारी दिवस के स्तर के मुकाबले ऊपर-नीचे होते रहे.

कोराबार की समाप्ति से पहले भी कुछ देर के लिए सेंसेक्स लाल निशान में गया था, लेकिन अंत में ऊपर बंद हुआ. बीच कारोबार में यह ऊपर 78,942.45 अंक तक और नीचे 78,203.30 अंक तक गया. प्रमुख सूचकांकों के विपरीत वृहत बाजारों में बिकवाली हावी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.19 फीसदी और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.45 प्रतिशत की गिरावट में बंद हुआ.

> सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेंट का शेयर सवा तीन प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा. भारतीय स्टेट बैंक में ढाई फीसदी, एशियन पेंट्स में दो फीसदी और एनटीपीसी तथा बजाज फाइनेंस में एक फीसदी से अधिक की तेजी रही. इंडिगो, इटरनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और पावरग्रिड के शेयर भी हरे निशान में रहे. एलएंडटी और बीईएल में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट रही. एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, सनफार्मा और टाइटन के शेयर भी टूट गये.

नया लेबर कोड : सैलरी पर बड़ा असर

नई दिल्ली, 20 अप्रैल. भारत में लागू हुए नए लेबर कोड के बाद कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी, भविष्य की बचत और रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा. अब सभी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि कर्मचारी का बेसिक वेतन कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत हो. अब तक कई कंपनियां टैक्स और लागत प्रबंधन के लिए बेसिक सैलरी को कम रखती थीं और बाकी हिस्से को ।क्र कन्वेयंस, बोनस और अन्य भत्तों के रूप में देती थीं. लेकिन नए नियमों के तहत यदि कुल सैलरी में भत्तों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है, तो उस अंतर को बेसिक पे में शामिल करना होगा.

चांदी में भारी गिरावट, सोना भी हुआ सस्ता

नई दिल्ली, 20 अप्रैल अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सर्राफा बाजार में सोमवार को तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जहां कीमती धातुओं की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

बीते सप्ताह की तेजी के बाद निवेशकों को बड़ा झटका लगा, जब चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब 5,000 प्रति किलो तक की गिरावट आ गई. वहीं, सोने के दाम भी दबाव में आकर नीचे फिसल गए, जिससे बाजार में अस्थिरता का माहौल बन गया है. जानकारी के मुताबिक, चांदी की कीमतें अपने हालिया उच्च

स्तर से लगभग 1.87 लाख तक सस्ती हो गई हैं. इस तेज गिरावट ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हाल के दिनों में चांदी ने मजबूत तेजी दिखाई थी और इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प माना जा रहा था. अब अचानक आई इस गिरावट को मुनाफावसूली और वैश्विक संकेतों में कमजोरी से जोड़कर देखा जा रहा है.

> अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं पर दबाव देखने को मिला है. भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर की मजबूती के चलते निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में कुछ समय के लिए जोखिम कम करना शुरू कर दिया है. इसी वजह से सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वैश्विक बाजार में चांदी में करीब 1.8% से अधिक की गिरावट देखी गई है, जबकि सोना भी दबाव में रहा है.

मार्च में खुदरा महंगाई 3.4 प्रतिशत पर पहुंची

नई दिल्ली, 20 अप्रैल. मार्च महीने में देश की खुदरा महंगाई दर 3.4 प्रतिशत दर्ज की गई, जो फरवरी के 3.21 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी अधिक है. यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई. मासिक आधार पर इसमें 0.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.63 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 3.11 प्रतिशत रही.

खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर मार्च में बढ़कर 3.87 प्रतिशत हो गई, जबकि फरवरी में यह 3.47 प्रतिशत थी.

औद्योगिक भूमि सुधार से मैन्युफैक्चरिंग तेज

नई दिल्ली, 20 अप्रैल भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में औद्योगिक भूमि सुधारों को एक निर्णायक कारक माना जा रहा है.

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि जब तक उद्योगों को किफायती, पारदर्शी और सुगम तरीके से भूमि उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक 'मेक इन इंडिया' और देश की मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह साकार नहीं हो सकतीं.

सीआईआई की रिपोर्ट 'सीआईआई लैंड मिशन: फ्रेमवर्क टू रिफॉर्म इंडस्ट्रियल लैंड मैनेजमेंट इन इंडिया' में औद्योगिक भूमि प्रणाली में मौजूद संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में देश के कई राज्यों में औद्योगिक भूमि से जुड़ी प्रक्रियाएं खंडित और जटिल हैं, जिससे निवेशकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है.

समाचार विशेष

अरूप रॉय लगा पाएंगे जीत का चौका?

क्या इस बार होगा कोई बड़ा उलटफेर

कोलकाता. नगर के ठीक दूसरी तरफ हुगली नदी के किनारे बसा हावड़ा मध्य विधानसभा क्षेत्र इन दिनों सियासी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है. साल 2026 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही यहां के बाजारों और गलियों में चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

यह क्षेत्र न केवल अपने घने शहरी बसावट और व्यस्त बाजारों के लिए जाना जाता है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के एक

मजबूत स्तंभ के रूप में भी उभरा है. 29 अप्रैल को जब इस क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो उनके सामने पुराने रिकॉर्ड और भविष्य की नई उम्मीदें दोनों होंगी. हावड़ा जिले के दिल में स्थित यह सामान्य श्रेणी की सीट सात विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जो हावड़ा लोकसभा सीट के दायरे में आती है.

हावड़ा मध्य का चुनावी नक्शा समय के साथ कई बार बदला है. साल 1951 से अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो इस क्षेत्र का भूगोल कई बार पुनर्गठित किया गया है. शुरुआत में इस इलाके में हावड़ा उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण जैसे चार निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे. साल 1967 के चुनावों से ठीक पहले हावड़ा सेंट्रल के रूप में एक नई सीट बनाई गई, जिसे बाद में साल 2006 के परिसीमन आयोग के आदेश के बाद हावड़ा मध्य का नाम दिया गया. वर्तमान में यह निर्वाचन क्षेत्र हावड़ा नगर निगम के 18 वार्डों को अपने दायरे में समेटे हुए है. 1967 से 2006 के बीच के चुनावी परिणामों को देखें तो यहां कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा जिसने छह बार जीत हासिल की, जबकि

तृणमूल के अजेय दुर्ग में सेंध लगाने की भाजपाई कोशिश

साल 2011 के बाद से हावड़ा मध्य की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया और यह पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य किला बन गया. अरूप रॉय इस क्षेत्र के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे जिन्होंने लगातार तीन बार जीत दर्ज की है. उन्होंने साल 2011 में माकपा के तत्कालीन विधायक को 50 हजार से अधिक वोटों के भारी अंतर से हराया था. इसके बाद 2016 में उन्होंने जदयू उम्मीदवार को शिकस्त दी और 2021 के चुनावों में भाजपा के संजय सिंह को 46,547 वोटों के अंतर से हराकर अपनी लोकप्रियता सत की.

पेरंबूर सीट कैडर की ताकत बनाम करिश्मा की लड़ाई

विजय की सेलिब्रिटी सीट पर मुद्दे जमीनी लेकिन अग्निपरीक्षा फिल्मी

चेन्नई. पेरंबूर सीट तमिलनाडु की राजनीति की सबसे बड़ी तजुर्बागाह है. यहां डीएमके के प्रत्याशी आर डी शेखर हैं, जो 2019 से विधायक हैं. उनके सामने लार्जर देन लाइफ उम्मीदों के साथ राजनीति में आए अभिनेता से नेता बने सी जोसफ विजय हैं, जिन्हें फैंस मोहब्बत से थलापति विजय कहते हैं.

पेरंबूर में 2 लाख 22 हजार 728 वोटर हैं. इनमें से 75,000 वोटर 18 से 23 साल उम्र के हैं. और 16,823 फर्स्ट टाइम वोटर हैं. वहीं 1.14 लाख महिला वोटर हैं.

पेरंबूर चेन्नई शहर की सीट है. जाहिर है, यहां जाति, समुदाय और क्लास मिलकर किस्मत तय करेंगे. दलित सबसे ज्यादा हैं, 15-20 प्रतिशत मुसलमान वोटर हैं. कुछ इलाकों में ईसाई समुदाय मजबूत है. ओबीसी से वन्नियार, मुडालियार, नायडू तीनों हैं, लेकिन अलग-अलग इलाकों में बिखरे हुए. दलित-मुसलमान डीएमके के पारंपरिक वोटर हैं, पर बात जब पानी, बिजली, ड्रेनेज जैसे मुद्दों की हो, तो पलट सकते हैं. अन्नाद्रमुक ऐसे में वोट काटने के रोल में है. पर विजय के पास जाति से ज्यादा डेमोग्राफी अहम होगी, यानी उम्र व इलाके.

डीएमके के राज्यसभा सांसद गिरिराजन का मानना है कि विजय के प्रशंसकों से मुकाबला करने के लिए उनके पास स्कीम हैं. कहते हैं, हमारे प्रत्याशी स्टूडेंट लीडर से विधायक बने हैं और विजय ने आज तक वार्ड का चुनाव भी नहीं लड़ा. वो सेलिब्रिटी हैं और हम सेवा कर रहे हैं.

विधानसभा चुनाव में गूंज रहा वीरप्पन का नाम

बेटी विद्यारानी और पत्नी मुथुलक्ष्मी ने ठोंकी ताल

नई दिल्ली. तमिलनाडु में एक पुलिस मुठभेड़ में खूंखार जंगल डाकू वीरप्पन के मारे जाने के दो दशक बाद, उसकी विरासत एक बार फिर तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गई है. वीरप्पन की बेटी विद्यारानी और पत्नी मुथुलक्ष्मी चुनावी मैदान में उतरकर उसे एक अपराधी के बजाय तमिल अधिकारों के रक्षक और रॉबिन हुड के रूप में पेश कर रही हैं.

दरअसल, वीरप्पन की बड़ी बेटी विद्यारानी पेशे से वकील हैं और विधानसभा क्षेत्र से नाम तमिलर काची (एनटीके) की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं. वहीं वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी तमिलगा वाझवुरिमाई काची की ओर से कृष्णागिरी से चुनावी मैदान में हैं. ये दोनों ही पार्टियां तमिल राष्ट्रवाद का समर्थन करती हैं.

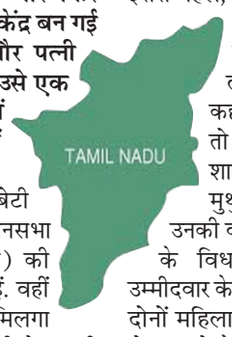

वीरप्पन की 35 वर्षीय बेटी विद्यारानी दूसरी बार चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, इससे पहले, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में कृष्णागिरी से एनटीके उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें एक लाख से ज्याद वोट मिले थे. विद्यारानी कहना है, अगर आज मेरे पिता जीवित होते, तो वे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ज़रूर शामिल होते. वहीं, वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी के लिए भी, यह राजनीति में उनकी वापसी का संकेत है, मुथुलक्ष्मी ने 2006 के विधानसभा चुनावों में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति में कदम रखा था. इन दोनों महिलाओं ने वीरप्पन की विवादित विरासत से कतराने के बजाय उसे खुले दिल से अपनाया है, और वे उसकी छवि को एक नए रूप में पेश करना चाहती हैं.

विशेष | **डीएमके-कांग्रेस गठबंधन की मजबूती पर गंभीर सवाल**

तमिलनाडु के चुनावी मैदान से क्यों दूर हैं राहुल?

चेन्नई. तमिलनाडु की राजनीति इस समय अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है. 23 अप्रैल को होने वाले मतदान की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है.

एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर टीवीके प्रमुख विजय भी अपनी पूरी ताकत झोंकते दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इस पूरे शोर-शराबे के बीच राजनीतिक हलकों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी

अब तक मैदान में क्यों नहीं उतरे हैं. गठबंधन के भविष्य और एकजुटता को लेकर उठ रहे इन सवालों ने तमिलनाडु की सियासी हवा में एक अजीब सी बेचैनी घोल दी है.

आमतौर पर देखा गया है कि जहां भी कांग्रेस जब किसी दल के साथ गठबंधन में होती है, वहां राहुल गांधी स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे आगे रहते हैं. लेकिन तमिलनाडु के मौजूदा परिदृश्य में ये तस्वीर काफी धुंधली दिखाई दे रही है. अब मतदान होने में गिनती के दिन का समय बचा है, फिर भी कांग्रेस खेमे की तरफ से राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं शेयर की जा रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव के इस निर्णायक मोड़ पर राहुल गांधी का गायब रहना केवल उनकी निजी पसंद नहीं बल्कि गठबंधन की आंतरिक खटास का संकेत हो सकता है.

पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो डीएमके और कांग्रेस के बीच तालमेल की भारी कमी साफ दिखाई देती है.

गठबंधन के भीतर बढ़ती बेचैनी

डीएमके के शीर्ष नेताओं के भीतर राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर एक गहरा डर घर कर गया है. उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ मंच शेयर नहीं करता है, तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है. विपक्ष इस स्थिति का फायदा उठाकर एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में जुटा है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है.